भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4650

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया गया

वित्तीय साक्षरता संबंधी सर्वेक्षण

4650. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (आर॰बी॰आई॰) ने देश की ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता को मापने के लिए सर्वेक्षण किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार परिणाम क्या रहे;

(ख) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता में सुधार करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने भी वित्तीय प्रणाली में शामिल किए गए नए लोगों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के लिए बैंकों और ग्रामीण शाखाओं के वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की सलाह दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी और सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकिंग एजेंटों के अनुपात का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की ग्रामीण आबादी की वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित किए गए अनुसार उन्होंने 29 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को छोड़कर) में समग्र भारत वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण का आयोजन किया है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत, वित्तीय साक्षरता का मूल्यांकन तीन घटकों, नामतः वित्तीय ज्ञान, मनोभाव एवं व्यवहार के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय ज्ञान, वित्तीय मनोभाव और वित्तीय व्यवहार के तीनों घटकों के लिए अधिकतम अंक क्रमशः 7, 5 तथा 9 है। इन तीनों घटकों के संबंध में भारत का औसत अंक क्रमशः 3.7, 2.6 तथा 5.6 है और वित्तीय साक्षरता के संबंध में कुल 21 अंक में औसत अंक 11.9 है।

आरबीआई द्वारा सूचित किए गए अनुसार, यद्यपि सर्वेक्षण के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में राज्य-वार वित्तीय साक्षरता अंक उपलब्ध नहीं हैं तथापि, उक्त अंक क्षेत्र-वार उपलब्ध है। विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में औसत अंक निम्नानुसार है-

क्षेत्र	**कुल वित्तीय साक्षरता अंक**	**शहरी**	**ग्रामीण**
उत्तर	11.5	11.5	11.5
पूर्व	12.1	12.1	12.1
मध्य	12.4	12.5	12.1
पश्चिम	12.6	12.6	12.5
दक्षिण	11.0	11.2	10.3

स्रोत: आरबीआई

(ग) से (ड़): आरबीआई ने दिनांक 14.01.2016 के परिपत्र के द्वारा बैंकों को एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता धारकों सहित वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की सलाह दी थी। तदनुसार, देश भर के बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ़एलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के द्वारा जनवरी 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान वित्तीय प्रणाली में शामिल किए गए नए लोगों के लिए आयोजित किए गए विशेष शिविरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	शिविरों की संख्या				
	जनवरी 16-मार्च 16	अप्रैल 16-जून 16	जुलाई 16-सितंबर 16	अक्तूबर 16-दिसंबर 16	जनवरी 17-मार्च 17
एफएलसी	5,990	7,838	9,501	11,676	9,591
ग्रामीण शाखाएं	34,115	38,568	37,983	36,918	37,528

स्रोत: आरबीआई

इसके अलावा, जैसा कि आरबीआई द्वारा सलाह दी गई है, वित्तीय साक्षरता शिविर एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। देश में एफ़एलसी और ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित इस तरह के शिविरों की संख्या निम्नानुसार हैं:

अवधि	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर तक)
एफएलसी	1,29,280	1,45,427	1,13,015
ग्रामीण शाखाएं	2,64,120	3,05,672	2,61,428

स्रोत: आरबीआई

जैसाकि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे गांवों में 5.41 लाख बैंकिंग सेवा केन्द्र थे। बीसी के माध्यम से गांवों में चलाए जा रहे बैंकिंग सेवा केन्द्रों के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध में दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की तुलना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग अभिकर्ताओं के अनुपात से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****

अनुबंध	
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार आंकड़े	
राज्य	**बीसी के माध्यम से गांवों में चलाए जा रहे बैंकिंग सेवा केन्द्रों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	479
आंध्र प्रदेश	22,759
अरुणाचल प्रदेश	2,497
असम	21,387
बिहार	42,536
चंडीगढ़	150
छत्तीसगढ़	15,613
दादरा और नगर हवेली	106
दमन और दीव	17
दिल्ली	1,087
गोवा	263
गुजरात	19,555
हरियाणा	9,428
हिमाचल प्रदेश	7,363
जम्मू और कश्मीर	3,516
झारखंड	25,676
कर्नाटक	26,117
केरल	2,728
लक्षद्वीप	-
मध्य प्रदेश	46,406
महाराष्ट्र	37,842
मणिपुर	2,263
मेघालय	4,315
मिजोरम	426
नागालैंड	803
ओडिशा	40,998
पुडुचेरी	92
पंजाब	11,062
राजस्थान	29,698
सिक्किम	1,170
तमिलनाडु	18,817
तेलंगाना	9,749
त्रिपुरा	751
उत्तर प्रदेश	90,613
उत्तराखंड	10,345
पश्चिम बंगाल	34,502
सकल योग	5,41,129

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

*****